(ग) इस तरह से कितने वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और सरकार द्वारा उन्हें आदिवासियों को सौंपने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) संगत सूचना एकत्र की जा रही है।

लुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजातियां

2437. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक जनजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं क्योंकि वे तेजी से बढ़ते आधुनिकीकरण के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाई और पक्षपातपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था को सहन नहीं कर पाई;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जनजातियां कितनी हैं और कौन-कौन सी हैं; और

(ग) क्या सरकार इन जनजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए कोई पहल कर रही है/करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनजातियों के संरक्षण और विकास करने के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिल क-आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ किये जाते हैं। भारत सरकार आदिम जनजाति समूहों के लिए विशेष आबंटन करती है तथा यहां तक कि सम्पूर्ण के सिद्धान्त पर भी बल नहीं देती है। आदिम समुदायों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर शुरू किए जाते हैं। आदिम जनजाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उनकी सहायता करने हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान आदिम जनजाति समूहों के विकास संबंधी एक नई योजना कार्यान्वित की जाएगी। प्रत्येक जनजाति तथा इसके पर्यावरण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना में अन्तःनिर्मित लचीलापन होगा।

Mining of Commercial Basis in Himachal Pradesh

2438. **SHRI ANIL SHARMA**: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the number of areas identified in Himachal Pradesh where mining can take place on a commerical basis;

(b) the steps taken to develop these areas so as to tap the national resources of Himachal Pradesh;

(c) the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Mining on a commercial scale is going on in Bilaspur district for limestone, in Mandi district for salt (rock), in Sirmur district for barytes and limestone and in Solan district for limestone and shale. Besides, five areas have been identified in Himachal Pradesh.

(b) and (c) The development of areas for exploitation of mineral resources is primarily the responsibility of the State Government. However, Geological Survey of India under the Ministry has carried out survey to identify mineral deposits.

The details of the five areas identified are as under:—

(i) Limestone: 292.010 hect., in Shind and Baroh Areas of Chamba district.

(ii) Limestone: 725.857 hect., in Surendranagar Mandi district and

(iii) Limestone: 450 hect., in village Alsindi in Mandi district.

(iv) Limestone: About 238 hect., near village Sujala in Solan district.

(v) Rock-salt: About 41.88 hect. in Darang area, Mandi district.

(d) Question does not arise.

SAIL Stock Yard at Dharmanagar

2439. **SHRI KHAGEN DAS**: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal for SAIL stock yard at Dharmanagar; and

(b) by when the stock yard will become functional?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Expansion of Production in Rashtriya Ispat Nigam

2440. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether according to the project report, Rashtriya Ispat Nigam (RIN) has the possibility of expansion of production upto ten million tonnes; and

(b) whether Government are taking steps to expand the capacity so that it becomes profitable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) The layout etc. of the Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (Visakhapatnam Steel Plant) admits expansion of capacity to 10 million tonnes.

(b) As per direction of the Govt., the company engaged an internationally reputed consultant to study the turnaround strategies and prepare a comprehensive revival plan for long term viability of the company. The consultants have since submitted their report. And a comprehensive proposal for the revival of the plant is under consideration.

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात एककों को स्थापित किया जाना

2441. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये इस्पात एककों से प्रत्येक एकक से वर्ष-वार कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) क्या किसी नये गैर-सरकारी उद्यम द्वारा एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात एककों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस्पात विभाग इस प्रकार की जानकारी का प्रबोधन नहीं करता।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार के पास औद्योगिक लाइसेंस हेतु कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

(घ) सरकार ने निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग में निवेश को सरल और सुसाध्य बनाने के लिए एक अनुकूल नीति संबंधी वातावरण सृजित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस को समाप्त करना, मूल्यों का विनियन्त्रण, विदेशी निवेशों के प्रयोजन हेतु उच्च प्राथमिकता उद्योग का दर्जा देना आदि शामिल हैं।

Fertiliser Production by VSP

2442. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fertiliser production at Visakhapatnam Steel Plant has fallen;

(b) the average fertilizer production last year;

(c) the reasons for the present fall;

(d) whether there are any plans for expansion of the total capacity of the plant; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Yes, Sir.

(b) The average fertilizer production last year was 2783 tonnes per month.

(c) The fall in production was due to less production of coke oven gas.

(d) and (e) As per directions of the Govt., the company engaged an internationally reputed consultant to study the turnaround strategies and